जनसत्ता

किसान की सुध

प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत एक करोड़ से ऊपर किसानों के खाते में सीधे दो हजार रुपए की पहली किश्त भेज दी गई है। अगले कुछ दिनों में बाकी किसानों के खाते में भी यह राशि पहुंचाने का वादा है। इस योजना के तहत देश के बारह करोड़ किसानों को साल के छह हजार रुपए तीन किश्तों में दिए जाने हैं। इस योजना की घोषणा अंतरिम बजट में की गई थी। इससे पचहत्तर हजार करोड़ रुपए का बोझ सरकार पर पड़ेगा। यह अकारण नहीं है कि प्रधानमंत्री ने इस योजना की पहली किश्त जारी करने के लिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को चुना। आम चुनाव नजदीक हैं और माना जा रहा है कि खासकर उत्तर प्रदेश के किसानों में नाराजगी कुछ अधिक है। फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के विधानसभा चुनावों में जिस तरह कांग्रेस ने किसानों की कर्जमाफी की घोषणा करके उन्हें लुभाने का प्रयास किया और उसके सकारात्मक नतीजे नजर आए, उससे भी केंद्र सरकार की कुछ चिंता बढ़ी है। इसलिए अंतरिम बजट में किसानों के लिए भारी-भरकम योजनाएं पेश की गईं। मगर देखने की बात है कि इन योजनाओं का किसानों पर कितना असर पड़ता है।

किसान सम्मान योजना के तहत दो हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों को साल में छह हजार रुपए की मदद मुहैया कराने की घोषणा है। यानी हर महीने पांच सौ रुपए। विपक्ष इस सत्रह रुपए रोज की मदद को किसानों के लिए नाकाफी बता रहा है। मगर केंद्र किसानों के हित में शुरू की गई दूसरी योजनाओं को भी अपनी उपलब्धि बता रहा है। छह हजार रुपए सालाना के अलावा किसान बिना शर्त बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए एक लाख साठ हजार रुपए निकाल सकते हैं। फिर सिंचाई परियोजनाओं पर भारी-भरकम रकम खर्च करने की योजना है। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। इस तरह केंद्र सरकार का दावा है कि कर्जमाफी से ज्यादा असरकारी ये योजनाएं हैं। कर्जमाफी से एक बार किसानों को लाभ मिलेगा, जबकि इन योजनाओं से पुश्तें लाभान्वित होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने इस बार के बजट में किसानों को ध्यान में रख कर कई योजनाएं शुरू की हैं। खासकर जबसे उत्तर प्रदेश में गोवंश के मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा है, बड़े पैमाने पर बछड़े फसलों को नुकसान पहुंचाते देखे जा रहे हैं। इस समस्या से पार पाना, तो सरकार की चिंता है ही, किसानों की बुनियादी समस्याओं का हल निकालना भी बड़ी चुनौती है। इसलिए इन योजनाओं से उन्हें राहत पहुंचाने का दावा किया जा रहा है।

खेती-किसानी की स्थिति छिपी नहीं है। हालत यह है कि अब खेती लाभ का सौदा नहीं रह गई है, इसलिए किसान वैकल्पिक रोजगार की तलाश में हैं। सबसे बुरी स्थिति छोटी जोत के किसानों की है। मगर लंबे समय से किसानों को ध्यान में रख कर कोई व्यावहारिक नीति नहीं बनाई जा सकी है, जिससे किसानी बेहतर आमदनी का जरिया बन सके। इसे लेकर समय-समय पर आंदोलन भी सिर उठाते रहे हैं। ऐसे में कर्जमाफी और पांच सौ रुपए महीने की मदद जैसे कदम से किसानों की स्थिति में कितना सुधार होगा, दावा नहीं किया जा सकता। इसलिए विपक्ष की किसानों की न्यूनतम आय गारंटी योजना की सिफारिश की तरफ स्वाभाविक रूप से लोगों का ध्यान जा रहा है। सिर्फ चुनाव की चिंता में किसानों के लिए योजनाएं बनाने के बजाय व्यावहारिक योजनाओं पर विचार की दरकार अब भी बनी हुई है।

शराब का कहर

असम में जहरीली शराब से बड़ी संख्या में मौतें दहला देने वाली हैं। इस घटना से यह अंदाज लगा पाना मुश्किल नहीं है कि उत्तर-पूर्व के इस सबसे बड़े राज्य में जहरीली शराब का कारोबार कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है। भले सरकार कुछ भी दावे करती रहे, लेकिन इतने लोगों की मौत इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि राज्य में जहरीली शराब के कालेधंधे पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। हालात की गंभीरता का अंदाजा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान से लगाया जा सकता है कि मरने वालों की संख्या हर मिनट बढ़ रही है। असम की यह दर्दनाक घटना गोलाघाट और जोरहाट जिले के चायबागानों की है जहां लोगों ने जहरीली शराब पी और उसके बाद तेजी से मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। मारे गए सभी लोग मजदूर तबके हैं। जाहिर है, सस्ती शराब का लालच इनकी मौत का कारण बन गया।

असम की यह घटना बताती है कि प्रशासन अगर सचेत रहता तो शायद यह हादसा टल सकता था। इस हादसे ने सरकारी तंत्र की लापरवाही को उजागर कर दिया है। साफ-सुथरा प्रशासन देने का वादा करने वाली सरकार के राज में अगर जहरीली शराब से इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे जाएं तो इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है! घटना के तुरंत बाद प्रशासन ने दो आबकारी अधिकारियों को निलंबित कर औपचारिकता पूरी कर ली। शराब के अवैध कारोबार को रोकने का पहली जिम्मेदारी आबकारी विभाग की विभाग की होती है। जाहिर है, इस महकमे ने ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, वरना जहरीली शराब कहां से आ रही है और कहां बन रही है, इसका समय रहते पता चल सकता था। इस घटना के बाद पुलिस और आबकारी विभाग ने जिले में बड़ी संख्या में कच्ची शराब की भट्ठियों को नष्ट कर दिया। पर सवाल है कि ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? क्या स्थानीय पुलिस को अवैध शराब बनाने वाली भट्ठियों के बारे में पता नहीं था? हैरानी की बात है कि पुलिस की नाक के नीचे शराब की भट्ठियां चल रही थीं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। कच्ची शराब सस्ती होती है और आसानी से मिल जाती है, इसलिए निम्न-वर्गीय बस्तियों में कच्ची शराब के मटके ज्यादा चलते हैं। पुलिस और प्रशासन इन्हें इसलिए चलने देता है, क्योंकि ये धंधे उगाही के बड़े स्रोत होते हैं। ऐसे में सौ लोगों की जान जाने के लिए क्या सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए?

अभी एक पखवाड़ा भी नहीं गुजरा है जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी जहरीली शराब से करीब सत्तर लोग मारे गए। इन राज्यों में जहरीली शराब का कारोबार करने वाले माफियाओं का दबदबा है। हालांकि पुलिस ने कुछेक जगह छापेमारी कर गिरफ्तारियां तो की हैं लेकिन इन धंधों के असली सरगना और उन्हें संरक्षण देने वाले पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। दरअसल शराब माफिया बेखौफ होकर कारोबार इसलिए करता है क्योंकि सरकारें उस पर हाथ डालने से परहेज करती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर सरकारें चाहें तो अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ा जा सकता है, लेकिन विडंबना यह है कि शक्तियों और अधिकारों से परिपूर्ण तंत्र भी शराब माफिया के सामने घुटने टेक देता है। इसी का नतीजा है कि धड़ल्ले से देशी शराब की भट्ठियां चलती हैं, जहरीली शराब भी बनती है और बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं।

कल्पमेधा

अगर इंसान सुख-दुख की फिक्र से ऊपर उठ जाए तो आसमान की ऊंचाई भी उसके पैरों तले आ जाए।
-शेख सादी

वैश्विक व्यापार में अवसर

जयंतीलाल भंडारी

भारत अमेरिकी उद्योग, कारोबार और कंपनियों के लिए नया निवेश केंद्र बन सकता है। चूंकि कई अमेरिकी कंपनियां लगातार चीन में उद्योग कारोबार करने में बढ़ती दिक्कतों की शिकायत कर रही हैं। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन में चीन से अच्छी स्थिति रखने वाला भारत अमेरिकी अर्थव्यवस्था में चीन की जगह ले सकता है।

इन दिनों भारत के लिए देश और दुनिया में नए आर्थिक मौके बढ़ने का परिदृश्य बन रहा है। एक ओर जहां भारत में तेजी से बढ़ती बौद्धिक संपदा के कारण ये मौके बढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर वैश्विक मंदी की आहट के बीच भारत के लिए नए अवसरों की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। हाल में अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवोन्मेष नीति केंद्र (जीआइपीसी) की ओर से जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (आइपी) सूचकांक 2019 में पचास अर्थव्यवस्थाओं में भारत ने छत्तीसवां स्थान हासिल किया है। यह 2018 में हासिल चवालीसवें स्थान से आठ स्थान ऊपर है। नया आइपी सूचकांक तैयार करते समय प्रतिस्पर्धात्मकता पर वैश्विक बाजार में आंकड़े आधारित विचार, कारोबारी समुदाय द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मानदंडों जैसे पैंतालीस क्षेत्रों के आंकड़ों को आधार बनाया गया है। जीआइपीसी के मापदंडों में व्यापार गोपनीयता का संरक्षण, पेटेंट और कॉपीराइट प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं। इन मापदंडों पर ज्ञान आधारित उद्योग-कारोबार का विकास, स्टार्टअप, घरेलू कारोबारियों और विदेशी निवेशकों के निवेश निर्भर करते हैं। जहां बौद्धिक अधिकार संपदा का एक पक्ष रचनात्मक होता है तो दूसरा पक्ष कारोबार से संबंधित होता है। रचनात्मक कार्यों के लिए कॉपीराइट का अधिकार होता है जबकि कारोबार के उद्देश्य से किए गए किसी आविष्कार को यह अधिकार पेटेंट के रूप में दिया जाता है।

पिछले दिनों दुबई में वैश्विक आर्थिक प्रबंधन शिखर सम्मेलन में नोबेल पुरस्कार विजेता अथर्शास्त्री पॉल क्रुगमैन ने चेतावनी दी कि दुनिया आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रही है और आर्थिक नीतियां बनाने वालों के बीच तालमेल और तैयारियों की कमी के कारण 2019 के अंत या फिर 2020 की शुरुआत में दुनिया वैश्विक आर्थिक मंदी की चपेट में आ सकती है। आर्थिक मंदी की ऐसी आशंकाओं को बढ़ते हुए वैश्विक व्यापार युद्ध और चीन की आर्थिक सुस्ती से भी बढ़ावा मिल सकता है। ऐसे में भारत के लिए आर्थिक चुनौतियों के बीच कई आर्थिक मौके उभरकर दिखाई दे रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि सात फरवरी को संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक व्यापार से संबंधित रिपोर्ट में कहा कि अमेरिका-चीन के बीच व्यापार युद्ध से वैश्विक कारोबार की गति धीमी हो सकती है। लेकिन भारत के निर्यात में वर्ष 2019 में 3.5 फीसद की वृद्धि हो सकती है। इसी तरह हाल ही में चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो (एनबीएस) ने कहा है कि चीन में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर वर्ष 2018 में घट कर 6.6 फीसद पर आ गई है। यह दर सन 1990 से यानी पिछले अट्ठाइस वर्षों में अब तक की सबसे धीमी जीडीपी वृद्धि दर है। इससे यह संकेत मिलता है कि चीन की अर्थव्यवस्था में धीमापन आ रहा है। ऐसे में अर्थविशेषज्ञों का कहना है कि चीन की मंदी भी भारत के लिए आर्थिक मौके बढ़ाने वाली हो सकती है।

गौरतलब है कि चीन की अमेरिका के साथ कारोबारी जंग से चीन में अमेरिका से आने वाले ऐसे सामान की आवक कम हो गई है जिनका निर्यात भारत भी चीन को करता है। भारत से चीन के बाजार में इन वस्तुओं का निर्यात अमेरिका-चीन के बीच कारोबारी जंग के चलते बढ़ गया है। ट्रंप प्रशासन के कठोर रुख के कारण अमेरिका की फर्में चीन के साथ सौदे करने में डर रही हैं। चीन इस समय श्रम आधारित उत्पादों के विनिर्माण से दूर हो रहा है। उसका ध्यान मूल्यवृद्धि और प्रदूषण घटाने पर केंद्रित होने से देश भर में इकाइयां बंद हो रही हैं। ऐसे में भारत से कपास, लौह अयस्क, कार्बनिक रसायन और विनिर्मित उत्पादों के लिए चीन में नई बाजार संभावना दिखाई दे रही है। पिछले साल जून से लेकर नवंबर 2018 के बीच भारत से चीन को निर्यात में बत्तीस फीसद बढ़ोतरी हुई। कार्बनिक रसायन, लौह अयस्क और कपास जैसे कच्चे माल की बड़ी मात्रा में चीन की जरूरत बढ़ती जा रही है। इन पदार्थों की हिस्सेदारी भारत से चीन को होने वाले 13.33 अरब डॉलर निर्यात बास्केट में 70 फीसद से ज्यादा है। निसंदेह चीन की अमेरिका के साथ चल रही कारोबारी जंग के कारण भारत से अमेरिका को निर्यात में वृद्धि हो रही है। यह भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि

अमेरिका में चीन से आयातित की जाने वाली कई वस्तुओं के आयात मे भारी कमी आई है।

चीन में आर्थिक मंदी और कामगार आबादी की कमी के कारण बढ़ती श्रम लागत बढ़ी है, इससे चीन में निवेश घट रहे हैं और औद्योगिक उत्पादन में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दुनिया के निवेशक बड़ी संख्या में चीनी बाजारों के बजाय नकदी का प्रवाह भारत समेत नई उभरती अर्थव्यवस्था वाले बाजारों की ओर प्रवाहित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत अमेरिकी उद्योग, कारोबार और कंपनियों के लिए नया निवेश केंद्र बन सकता है। चूंकि कई अमेरिकी कंपनियां लगातार चीन में उद्योग कारोबार करने में बढ़ती दिक्कतों की शिकायत कर रही हैं। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन में चीन से अच्छी स्थिति रखने वाला भारत अमेरिकी अर्थव्यवस्था में चीन की जगह ले सकता है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत चीन और पश्चिमी देशों को पछाड़ कर दुनिया का नया कारखाना बन सकता है। स्थिति यह है कि कई आर्थिक मापदंडों पर भारत अभी भी चीन से आगे है। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में भारत ने विश्व की एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के तौर पर पहचान बनाई है। भारत के पास कुशल पेशेवरों की फौज है। आइटी, सॉफ्टवेयर, बीपीओ, फार्मास्युटिकल्स, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, रसायन एवं धातु क्षेत्र में दुनिया की जानी-मानी कंपनियां हैं। आर्थिक व वित्तीय क्षेत्र की शानदार संस्थाएं हैं। वैश्विक आर्थिक अध्ययन बता रहे हैं कि आने वाले वर्षों में भारत दवा निर्माण, रसायन निर्माण और जैव-तकनीकी के क्षेत्रों में सबसे तेजी से उभरने वाला देश बनेगा। भारत की श्रमशक्ति का एक सकारात्मक पक्ष यह है कि इस समय भारत में श्रम लागत चीन की तुलना में सस्ती भी है। भारत की पहचान प्रतिभाओं के गढ़ के रूप में है। इसमें कोई दो-मत नहीं कि उद्योग-कारोबार और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न प्रयासों से भारत दुनिया के परिदृश्य पर तेजी से उभरता हुआ दिखाई दे रहा है।

भारत में सूचना-प्रौद्योगिक क्षेत्र में नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के लिए दुनिया की कंपनियां तेजी से कदम बढ़ा रही हैं। अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों की बड़ी-बड़ी कंपनियां नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय आइटी प्रतिभाओं के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत में अपने ग्लोबल इन हाउस सेंटर (जीआइसी) खोल रही हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमता और डाटा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए लागत और प्रतिभा के अलावा नई प्रोद्यौगिकी पर नवोन्मेष और स्टार्टअप माहौल के चलते दुनिया की कंपनियों ने भारत की ओर रुख किया है। देश में जिस तरह प्रतिभाओं का उपयोग बढ़ रहा है, उसी तरह से एक बार फिर इस समय अमेरिका सहित दुनिया के अधिकांश देशों में भारतीय प्रतिभाओं के लिए नई संभावनाएं बन रही हैं।

यदि हम देश की बढ़ती हुई बौद्धिक संपदा दुनिया में आर्थिक मंदी की आशंकाओं, चीन की घटती हुई विकास दर और अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध के परिदृश्य के बीच उभरते हुए नए आर्थिक मौकों को अपनी मुट्ठियों में लेना चाहते हैं तो हमें कई बातों पर ध्यान देना होगा। हमें आर्थिक सुधार तेजकरने होंगे। देश में कर सरलीकरण को आगे बढ़ाना होगा। जीएसटी को सरल करना होगा। निश्चित रूप से ऐसा होने पर ही भारत विकास की डगर पर तेजी से आगे बढ़ेगा।

केतकी से ट्यूलिप तक

अरुणेंद्र नाथ वर्मा

दुनिया मेरे आगे

वसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा करते हुए प्रकृति के उल्लास का उत्सव मनाने वाली कई सारी कविताएं मन में सजीव हो उठीं। खेतों में झूमती हुई सरसों के साथ नटखट पवन के अल्हड़ खिलंदड़ीपन का जो शब्दचित्र केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी 'बसंती हवा' शीर्षक वाली कविता में खींचा है, उसे पढ़ कर भूल जाना संभव नहीं। उतनी ही कालातीत है वह उर्दू नज्म 'लो फिर बसंत आई', जो बेगम मलिका पुखराज और उनकी बेटी ताहिरा सैयद की सादगी भरी गायकी से अमर हो गई। निराला की 'विजन वन वल्लरी पर सोती सुहाग भरी स्वप्न मग्न जूही की कली' भी याद आई, जिसके साथ उद्दंडता और धृष्टता के लिए पवन को उकसाने वाली वासंती निशा ही थी। वसंत की छवि को अमरत्व प्रदान करने वाला जैसा काव्य कालिदास के 'ऋतुसंहार' में है, उसकी चर्चा कैसे न होती!

कविता के बाद बारी आई संगीत की। उसमे भी तो बसंत ऋतु को पूरा सम्मान दिया गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में शायद वर्षा ऋतु पर ज्यादा रचनाएं हैं, लेकिन राग बसंत में ऋतुराज का महिमामंडन किसी से कम नहीं। तो फिर बसंत पंचमी पर एक बार फिर वह गीत सुना, जिसे पंडित भीमसेन जोशी और मन्ना डे जैसे दो दिग्गजों की जुगलबंदी ने अविस्मरणीय बना दिया है। 1956 में बनी फिल्म 'बसंत बहार' में शंकर जयकिशन द्वारा संगीतबद्ध शैलेंद्र का गीत 'केतकी गुलाब जुही चम्पक बन फूले' जब भी सुनता हूं, रोमांचित हो जाता हूं। भारतरत्न भीमसेन जोशी और मन्ना डे की तानों से बुने गए राग बसंत के अद्भुत सम्मोहन से निकल कर मैंने जब परिवार की युवा होती पीढ़ियों से इस गीत के विषय में बात की तो पता चला कि वे केतकी के फूल से अपरिचित थीं।

उनका प्रश्न बसंत की भावभीनी दुनिया से वापस यथार्थ की कड़ी जमीन पर ले आया। जिस केतकी से मेरे परिवार की कोंपलें अपरिचित थीं, उसके अतिरिक्त गुलाब, बेला, चमेली के उत्पादन के लिए मेरा जन्मस्थान गाजीपुर पिछली सदी के पूर्वार्ध तक विख्यात था। इस सुवासित फूल का पेड़ छोटी से मध्यम ऊंचाई का होता है। उसकी लंबी नुकीली और मोटी पत्तियों की पीठ और किनारे कांटेदार होने के कारण उन्हें तोड़ना कष्टदायी हो सकता है। केतकी दो तरह की होती है- श्वेत और पीले फूलों वाली। श्वेत फूलों वाली केतकी का आम नाम है केवड़ा और पीले फूलों वाली का स्वर्णकेतकी। बरसात के दिनों में केवड़े पर सुवासित फूल खिलते हैं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार बंगाल आदि में यह पौधा खूब उगता है और आमतौर पर पानी की छोटी-छोटी पोखरियों के किनारे खुद उग आता है। केवड़े के फूल से गुलाबजल की तरह सुवासित केवड़ाजल बनाया जाता है। मोगलाई और अवध के सामिष व्यंजनों और खीर, सेवई आदि मिष्टान्न को केवड़ा जल से सुगंधित बनाया जाता है। पान के साथ लगाने वाले कत्थे पेस्ट में भी केवड़ा जल मिलाया जाता है। आज से छह-सात दशक पहले तक गाजीपुर में केवड़ा, गुलाब, बेला, चमेली आदि की खेती होती थी। शहर के बाहर इन फूलों के खेतों से घिरे एक गांव का नाम ही फुल्लनपुर था। लेकिन जब पारंपरिक अतर की जगह रसायनों से बनी कृत्रिम सुगंध ने ले ली है तो कौन इन फूलों को पूछे। फिर बेला-चमेली और देसी गुलाब के फूलों की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी छोटी दांडी और संक्षिप्त जीवन होता है। लंबे डंठलों वाले सुगंधरहित विदेशी गुलाब इस जमीन को भाते नहीं और महानगरों और विदेशों तक की यात्रा कर सकें, वैसे ये देशी सुगंधित फूल नहीं। विदेश यात्राओं के दौरान मैंने नीदरलैंड, फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका में फूलों के लंबे-चौड़े नयनाभिराम खेत देखे हैं। ट्यूलिप और डैफोडिल्स के हजारों फूलों के बगानों को एक बार देखने के बाद उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। इन फूलों और उनके बल्बों के निर्यात से ये देश जितना धनार्जन करते हैं, उसकी हमारे किसान कल्पना भी नहीं कर सकते।

कश्मीर में सिराजबाग के इंदिरा गांधी ट्यूलिप उद्यान में जैसे ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन देशी-विदेशी पर्यटकों को आकृष्ट करता है वैसे ही हिमाचल, उत्तराखंड आदि राज्यों में भी ट्यूलिप और डैफोडिल के लिए बहुत संभावनाएं हैं। हाल में ही की गई यह घोषणा सुखद है कि पिथौरागढ़ जिले में पचास एकड़ जमीन में ओएनजीसी के सहयोग से उत्तराखंड सरकार ट्यूलिप के फूलों की खेती शुरू कराएगी। भारत के पर्वतीय राज्यों में ट्यूलिप की खेती हॉलैंड के पैमाने पर प्रारंभ हो जाए तो पर्यटन से लेकर निर्यात तक धनार्जन की प्रबल संभावनाओं का अंदाज इसी से लग जाएगा कि पिथौरागढ़ के प्रायोजित ट्यूलिप फार्म के लिए कई करोड़ रुपयों के ट्यूलिप बल्ब हालैंड से मंगाए जाएंगे। मेरा मन अगले वर्ष की वसंत पंचमी का स्वागत करने के लिए अभी से आतुर है। पंडित भीमसेन जोशी और मन्ना डे दोनों अब नहीं रहे। लेकिन कौन जाने, ट्यूलिप के इन बागों में पधारते वसंत को देखकर एआर रहमान पश्चिमी और हिंदुस्तानी संगीत के फ्यूजन से 'ट्यूलिप डैफोडिल गुलाब संग चम्पक बन फूले' जैसा कोई गीत रच डालें!

नफरत का माहौल

पुलवामा हमले को कुछ ही दिन बीते हैं और राजनीतिक दलों ने इसका फायदा उठाना भी शुरू कर दिया है। सभी दल एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। समाचार चैनलों का स्टूडियो जंग का मैदान बना हुआ है। हमले के बाद से देश में नफरत का माहौल है। देश के अलग-अलग हिस्सों में कश्मीरी छात्रों और नागरिकों को हिंसा व अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खूब देखने को मिल रही हैं। शहीद जवानों के प्रति हमें सहानुभूति है, लेकिन इस तरह की घटनाओं से हम क्या साबित करना चाह रहे हैं। कश्मीर के लोग भी हमारे ही देश के नागरिक हैं। अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की घटना हमें एक-दूसरे से दूर कर देगी। देश जिस दौर से गुजर रहा है ऐसे में हमें एक-दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है।

● *मोहम्मद आसिफ, दिल्ली*

सेना पर हो विश्वास

आतंकी हमले के बाद से जिस तरह देश में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे, उसको लेकर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया कि क्या आतंकवाद और पाकिस्तान एक हैं? क्या पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स आतंकवादी है? इसके बीच जो सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, वो यह है कि क्या ऐसे सवाल करने वाले लोगों को अपनी सेना पर विश्वास नहीं है? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि भारतीय सेना पाकिस्तान की जनता को नुकसान पहुंचाने की सोच सकती है? क्या भारतीय सेना को आतंकवादी और बेगुनाहों में अंतर नजर नहीं आता? यह सभी सवाल उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसे सवालों को जन्म दिया। जरूरत है कि भारतीय सेना पर विश्वास किया जाए न कि ऐसे सवाल करके लोगों को भ्रमित किया जाए।

● *निशांत रावत, दिल्ली*

संवेदनशीलता की जरूरत

हाल ही में हुए पुलवामा हमले में सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए। जवानों की मौत के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है और इस गुस्से का शिकार देशभर में मौजूद कश्मीरियों को बनाया जा रहा है। एक तरफ भारत कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है, वहीं दूसरी तरफ कश्मीरियों के साथ हिंसा की जा रही है। ये कैसी दोहरी मानसिकता है? कश्मीर काफी समय से आतंकवाद की आग में झुलस रहा है और कश्मीरी लोग भी इसके शिकार हैं। यह समय गुस्से से नहीं, बल्कि संयम और सूझबूझ से काम लेने का है। लोगों को अपनी संवेदना प्रकट करते हुए कश्मीरियों के साथ प्यार और सद्भाव के साथ पेश आना चाहिए। देश में शांति बनाए रखने का काम सिर्फ सैनिकों का ही नहीं है, बल्कि देश की जनता और सरकार का भी है।

● *नेहा, दिल्ली*

दिखावा है लोकशाही

कई पश्चिमी देशों में शिक्षकों को समाज का अति महत्त्वपूर्ण और सम्मानित व्यक्ति माना जाता है, लेकिन भारत जैसे देश में वीआइपी उन्हें समझा जाता है जिनके पास धन हो, ओहदा हो, नाम हो। इसीलिए आज विश्व में सबसे अधिक वीआइपी भारत में ही पाए जाते हैं। इनकी संख्या 5.79 लाख से भी अधिक है। चीन में सिर्फ 435 लोग ही इस श्रेणी में आते हैं। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन व जापान जैसे विकसित देशों में भी इनकी संख्या 50 से 200 के अंदर है। मतलब भारत से राजे-रजवाड़े, मुगल और अंग्रेज गए, लेकिन उनकी जीवन शैली और ठाठ नहीं गया। सरकार को इन लोगों की सुरक्षा पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। 2013 के आंकड़े के अनुसार सिर्फ दिल्ली में ही वीआइपी लोगों की सुरक्षा में पुलिस के 8 हजार जवानों की तैनाती की गई थी। इसलिए कहा जा सकता है कि हम राजशाही व्यवस्था में रहते हैं, लोकशाही तो सिर्फ दिखावा है।

● *जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर*

चुनौती बनता नशा

मौजूदा समय में मादक पदार्थों का सेवन एक बड़ी चुनौती बन चुका है। युवाओं का एक बड़ा वर्ग इसकी चपेट में आ गया है। कुछ लोगों को नशे की ऐसी लत लग जाती है कि वे चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाते हैं। देश के कई राज्यों में मादक पदार्थों को चोरी-छिपे बेचा जा रहा है। पंजाब में तो नशीले पदार्थों के सेवन ने विकराल रूप धारण कर लिया है। नशे के कारण ही महिलाओं से छेड़खानी, बलात्कार, हिंसा, आत्महत्या, सड़क दुर्घटना, हत्या, बाल शोषण व घरेलू हिंसा जैसे अपराध भी होते हैं। मादक पदार्थों की लत में लोग अपनी जमा-पूंजी तक बर्बाद कर देते हैं और कई लोग तो इसके लिए चोरी तक करने लग जाते हैं। मादक पदार्थों से जुड़ी एक रिपोर्ट पर नजर डालें तो पता चलता है कि शराब के सेवन से हर साल 33 लाख लोगों की मौत होती है। भारत के कुछ राज्यों में शराब पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन इसका कुछ खास असर नहीं दिख रहा है। जब तक लोग खुद नशे की लत छोड़ना नहीं चाहेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता।

● *निखिल कुमार झा, दिल्ली विश्वविद्यालय*

मातृभाषा को मिले बढ़ावा

मातृभाषा को लुप्त होने से बचाने के लिए और इसे बढ़ावा देने के लिए 21 फरवरी का दिन मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की यह सराहनीय पहल भाषाओं को सहेजने और उन्हें पहचान दिलाने की दिशा में अच्छा प्रयास है क्योंकि मातृभाषा संप्रेषण का जरिया तो है ही, साथ ही यह समाज और लोगों को जोड़े रखने का भी कार्य करती है। आज अंग्रेजी के बढ़ते वैश्विक प्रभाव के कारण लोग अपनी मातृभाषा बोलने में असहज महसूस करते हैं और खुद को अंग्रेजी बोलने वाले से कमतर समझते हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में ही अनेक भाषाएं अपना अस्तित्व खो चुकी हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। सरकार को मातृभाषाओं को बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए ताकि कोई भी प्रतिभा भाषा की आड़ में दबकर न रह जाए।

● *प्रदीप कुमार सारण, बीकानेर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

नई दिल्ली